मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप सर्किट, तनोट माता व पूंछरी का लौठा के विकास कार्यों की समीक्षा की

उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने के निर्देश दिए

जयपुर, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास के साथ-साथ राज्य सरकार आस्था धामों और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर और धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास और पुनर्विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए विशेष प्रकोष्ठ के गठन के निर्देश दिए।

शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, पूंछरी का लौठा और तनोट माता मंदिर के विकास और पुनर्विकास कार्यों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित कराने तथा उनके शौर्य की गाथा जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, जैसे चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए 100 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

शर्मा ने अधिकारियों को जैसलमेर स्थित तनोट माता मन्दिर में पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा करने तथा श्रद्धालुओं के ठहरने की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा और गोवर्धन परिक्रमा के प्रगतिरत विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया में गति लाने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि विभिन्न चरणों में विकसित होने वाले इस पावन धाम पर श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएं।

बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, पूंछरी का लौठा और तनोट माता मंदिर के विकास और पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में उनके जीवन से जुड़े विभिन्न स्थल, जैसे चांवड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिनेर व उदयपुर आदि शामिल किये गये हैं तथा इनके लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।**

सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गुरुवार को बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करते हुए बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी।

सीबीएसई ने पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले डेटशीट जारी की है। दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च तक और 12वीं की 17 फरवरी से 09 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं विषयों के अनुसार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई ने कहा कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाले दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया है, और बोर्ड परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

भारतीय सेना के "त्रिशूल" सैन्य अभ्यास से दहला पाकिस्तान

यह अभ्यास पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। भारत के मेगा त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास त्रिशूल ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देना है कि भारत अपनी सीमा की रक्षा के लिए मुस्तैद है और आवश्यकता पड़ने पर मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति में और आगे कदम उठाने को भी तैयार है।

भारत ने गुरुवार को त्रिशूल की शुरुआत के साथ अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। यह 12 दिनों तक चलने वाला एक त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास है, जो पाकिस्तान सीमा पर आयोजित हो रहा है, और यह ऑपरेशन सिंदूर के छह महीने बाद भारत के पहले युद्धाभ्यास के रूप में सामने आया है।

त्रिशूल में विशेष बलों (स्पेशल फोर्सेज) के कमांडो, मिसाइल बैटरियां, युद्धपोत, युद्धक टैंक, और हमला करने वाले विमान, जिनमें राफेल और सुखोई एस यू-30 शामिल हैं, पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में आक्रामक हमलों का अभ्यास करेंगे, ताकि, सिंदूर के बाद के परिदृश्य में, भारतीय सशस्त्र बलों की तत्परता का परीक्षण हो सके।

यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान में होगा, लेकिन ध्यान विशेष रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर केन्द्रित होगा, जो पाकिस्तान के साथ एक नया सीमा विवाद स्थल हो सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने के शुरू में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह भारत के हिस्से वाले सिर क्रीक को अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश न करें, जो गुजरात के कच्छ रण और पाकिस्तान के बीच स्थित एक संकरी और विवादित जल-पट्टी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर से कम है।

कागजों पर यह दोनों देशों के बीच धुर पश्चिमी सीमा है; अर्थात, क्रीक का पश्चिमी भाग पाकिस्तान का है और पूर्वी भाग भारत का। राजनाथ सिंह ने गर्जना के स्वर में कहा था कि भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने के किसी भी प्रयास का जवाब "इतिहास और भूगोल" को बदल कर रख देगा।

- **तीनों सेनाओं का यह 12 दिवसीय अभ्यास गुजरात व राजस्थान में हो रहा है, पर इसका प्रमुख फोकस गुजरात में कच्छ का रन क्षेत्र है।**

चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों में भारत को मिली छह महीने की छूट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रैस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर चल रही कवायद के बीच चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध के मामले में भारत को अमेरिका से बड़ी तात्कालिक राहत मिली है, जिसमें अमेरिका ने बंदरगाह के संचालन पर लगाये गये प्रतिबंधों में छह महीने की छूट दे दी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरूवार को यहां साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस संबंध में पूछे गये सवाल के जवाब में कहा," हमें बंदरगाह पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट दी गई है।"

अमेरिका ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगायी गई पाबंदियों के मद्देनजर भारत के चाबहार बंदरगाह के संचालन को लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

भारत ने इस बंदरगाह को संचालन के लिए दस वर्ष के लिए लीज पर लिया हुआ है।

अमेरिका ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके संचालन पर 29 सितम्बर से जुर्माना लगाया जायेगा। बाद में कहा गया कि ये प्रतिबंध एक महीने बाद यानी, 27 अक्टूबर से लागू होंगे। अब भारत को छह महीने, यानी आगामी अप्रैल तक प्रतिबंधों में छूट दे दी गयी है।

भारत के लिए यह बंदरगाह अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी रूस तक व्यापार के लिए सुगम मार्ग प्रदान करता है।

इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच 2016 में समझौता हुआ था।

उल्लेखनीय है कि डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान भी भारत को चाबहार बंदरगाह के मामले में छूट दी गयी थी।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बारे में पूछे गये सवाल पर प्रवक्ता ने कहा, "हम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं।"

रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंधों से जुड़े सवाल पर जायसवाल ने कहा कि हम इन प्रतिबंधों के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं।

रूस से तेल की खरीद पर भारत के दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा कि भारत बाजार के उथल-पुथल भरे माहौल में अपने 140 करोड़ लोगों को सस्ते तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के रूख पर पर कायम है तथा राष्ट्रीय हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा।

- **अमेरिका ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगायी गई पाबंदियों के मद्देनजर भारत के चाबहार बंदरगाह के संचालन को लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की थी।**
- **भारत ने इस बंदरगाह को संचालन के लिए दस वर्ष के लिए लीज पर लिया हुआ है।**
- **भारत के लिए यह बंदरगाह अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी रूस तक व्यापार के लिए सुगम मार्ग प्रदान करता है।**

अब तीसरी कक्षा से एआई की पढ़ाई होगी

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर। शिक्षा मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में कक्षा तीन से आगे एआई पर पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा के आवश्यक घटकों के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए आज अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (एआई और सीटी) सीखने, सोचने और सिखाने की अवधारणा को सुदृढ़ करेगी और धीरे-धीरे "सार्वजनिक हित के लिए एआई" के विचार की ओर विस्तारित होगी। यह पहल जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए एआई के नैतिक उपयोग की दिशा में एक नया, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह तकनीक कक्षा तीन से शुरू होगी।

- **शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की और बताया कि सीबीएसई ने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।**

बूसान में हैंड शेक के बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पृथक्करण और चुंबक निर्माण की क्षमता अभी भी नहीं है। परिणामस्वरूप, भारत वही प्रसंस्कृत सामग्री आयात करता है, जिसे वह सिद्धांत रूप में स्वयं उत्पादन कर सकता है।

खान मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "भारत की निर्भरता संरचनात्मक है, न कि परिस्थितिजन्य, "हमारे पास अयस्क (ओर्स) हैं, लेकिन तकनीक नहीं है। बुसान समझौता सांस लेने की जगह देता है, स्वतंत्रता नहीं।"

यह समझौता निकट भविष्य में भारतीय उद्योग के लिए फायदेमंद है। कम कीमतें और आश्वस्त आपूर्ति से ईवी, पवन, और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, और सुज़लोन को उत्पादन की योजना बनाने में मदद मिलेगी, वो भी बिना उतार-चढ़ाव के। लेकिन खनन और प्रसंस्करण कंपनियां दबाव महसूस कर सकती हैं। परमाणु खनिज निदेशालय के पूर्व निदेशक के. राजन चेतावनी देते है, "अगर चीन उत्पादन बढ़ाता है, तो कीमतें गिर जाएंगी, जो स्थानीय प्रसंस्करण निवेश को हतोत्साहित करेगा। कम लागत की बजाय स्थिरता चाहिए।"

भारत एक महत्वपूर्ण खनिज रणनीति तैयार कर रहा है, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी पृथक्करण और चुंबक निर्माण के लिए 5,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना और शहरी खनन से रीसायक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ का पुश शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का तीसरा स्तंभ बनाना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ।

लेकिन ट्रंप-शी का यह समझौता उस गति को कमज़ोर कर सकता है। यदि पश्चिमी देश सहज हो जाते हैं, तो भारत साझेदारियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आकर्षित करने के लिये संघर्ष कर सकता है। आईआईटी मद्रास के प्राफेसर राजीव मल्होत्रा कहते है, "चीन की ताकत खनन में नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, पेटेंट और चुंबक निर्माण में है, भले ही एक साल के लिए कीमतें कम हों, पर तकनीकी अंतर बना रहता है।"

दुर्लभ पृथ्वी तत्व केवल अर्थशास्त्र का नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी मामला है। ये रडार प्रणालियों, सटीक मिसाइलों और स्टेल्थ विमानों का आधार हैं। भारत ने चुपचाप ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ आपूर्ति संबंधों को बनाना शुरू कर दिया है और स्टॉक भी बनाया है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा, "यह एक खिड़की है, समाधान नहीं, जब समझौता समाप्त होगा, असुरक्षाएं फिर से लौट आएंगी। हमें इस समय का उपयोग क्षमता बनाने के लिए करना चाहिए।"

भारत आखिरकार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को परमाणु उत्पादकों के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक संपत्तियों के रूप में पहचानने लगा है। आईआरईएल ने निजी कंपनियों के साथ पायलट प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की हैं, जबकि कंपनियां, जैसे सोना कॉमस्टार, घरेलू चुंबक निर्माण का अन्वेषण कर रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छ शोधन तकनीकों के लिए वित्त पोषण कर रहा है। लेकिन सरकारी बाधाएं, कमजोर अनुसंधान और विकास, और पर्यावरणीय संवेदनशीलताएं निवेशकों को निरुत्साहित करती हैं।

इसलिए, "बुसान हैंड शेक" कोई मोड़ नहीं है, केवल एक विराम है। एक साल की शांति भारत के लिए अपनी महत्वपूर्ण खनिज नीति को तेजी से लागू करने, प्रौद्योगिकी गठजोड़ बनाने और निष्कर्षण से लेकर अंतिम उपयोग निर्माण तक जाने का बूस्टर होनी चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता, आखिरकार, आयात नहीं की जा सकती। इसे शुद्ध किया जाना चाहिए, ठीक वैसे, जैसे वे खनिज, जो आधुनिक दुनिया को घुमाते हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53 वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल करीब 15 महीने का होगा। वह फरवरी 2027 में सेवानिृत होंगे। उन्हें मई 2019 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

इससे पहले वह 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को जन्में न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने 1984 में कानून की पढ ाई पूरी करने के बाद हिसार के जिला न्यायालय में वकालत शुरू की और उसके बाद 1985 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ में वकालत की। वे जनवरी 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश बनें। वे संवैधानिक, सेवा और सिविल मामलों के विशेषज्ञ हैं।

मनीष शर्मा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बजाय तेजस्वी ने उन्हें अपने घर मीटिंग में आने तक से रोक दिया। अब एक और असफल नेता अविनाश पांडे को बिहार भेजा गया है ताकि वह फिर से चीजों को सुलझा सकें। राहुल गांधी के साथ हमेशा प्रयाग करते रहते है और के.सी. वेणुगोपाल या नए समूह को जिम्मेवारी देत रहते हैं, जो या तो उन्हें गुमराह कर रहे हैं आर उन्हें सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता इस नियुक्ति से स्तब्ध हैं और कह रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं सुना।

ट्रंप और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आपूर्ति जारी रखने पर सहमत हो गया है। रेअर अर्थ मेटल और महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति बहाल होने से अमेरिका के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को काफी राहत मिलेगी।

17 बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित की पुलिस मुठभेड में मौत

मुंबई, 30 अक्टूबर। मुंबई के पवई इलाके में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गयी और पुलिस ने सभी बच्चों को सकुशल मुक्त करा लिया।

रोहित आर्या नाम के शख्स ने 17 बच्चों को गुरुवार को बंधक बना लिया। बच्चों को छुड़ाने के दौरान रोहित ने पुलिस पर गोली चला दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गयी।

मुंबई में उस समय तनाव की स्थिति बन गयी, जब आरए स्टूडियो में गुरुवार को 17 बच्चों को बंधक बनाये जाने की खबर फैली। बच्चे शहर के विभिन्न हिस्सों से ऑडिशन में भाग लेने के लिए स्टूडियो पहुँचे थे। रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने बच्चों को बंधक बना लिया। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक स्टूडियो पहुंचे। पुलिस भी उसी दौरान मौके पर पहुंच गयी।

पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी कर की और इलाके के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने आपातकालीन सेवाओं को भी तैनात कर दिया था। इसी दौरान, आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिससे मामला और भी ज़्यादा गरमा गया। वीडियो में रोहित ने कहा कि उसने अपनी जान देने की बजाय, बच्चों को बंधक बनाने का फैसला किया है। उसने कहा कि उसकी कुछ साधारण और नैतिक मांगे हैं और वह कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता है। आर्या ने वीडियो में यह भी कहा कि वह आतंकवादी नहीं है और उसकी कोई आर्थिक माँगें नहीं हैं। उसने कहा कि उसने एक योजना के तहत बच्चों को बंधक बनाया है। साथ ही, उसने धमकी दी कि किसी ने जरा सी भी गलती की तो वह पूरे परिसर में आग लगा देगा।

पुलिस ने लगातार प्रयासों के बाद स्टूडियो से सभी 17 बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया और रोहित को हिरासत में ले लिया।

- **सूत्रों के अनुसार पुलिस जब बच्चों को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी तब आरोपी ने गोली चला दी पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई जिससे आरोपी घायल हो गया व अस्पताल में उसकी मौत हो गई।**

पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी तालिबान को धमकाया

इस्लामाबाद, 30 अक्टूबर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें पूर्ण विनाश की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें तोरा बोरा गुफाओं में वापस भागने पर मजबूर कर देगा।

आसिफ ने बुधवार को एक्स पर प्रकाशित एक कड़े शब्दों वाले बयान में कहा कि इस्लामाबाद को तालिबान शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का एक अंश भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने तालिबान शासन पर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने और युद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पहले से ही युद्ध से तबाह अपने देश को एक और युद्ध में घसीटने का आरोप लगाया।

विश्व में तीसरे शीत युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीच के वर्षों में अमेरिका और रूस अपने परमाणु भंडारों के निर्माण को रोकने पर सहमत हुए थे, हालांकि, चीन ने गुपचुप तरीके से अपने हथियारों की संख्या बढ़ाई और अब वह लगभग अमेरिका और रूस की बराबरी पर आ गया है।

रूस और अमेरिका के पास लगभग 1,550 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास लगभग 1,000 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इनके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़रायल के पास भी परमाणु हथियार हैं, और कुछ अन्य देश भी इस दिशा में प्रयासरत हैं।

इतने विशाल परमाणु भंडार हैं कि यदि इनका केवल एक हिस्सा भी विस्फोटित हो जाए, तो पूरी दुनिया में प्रलय जैसी स्थिति बन जाएगी और मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। इंसान शायद फिर से गुफाओं में लौटने को मजबूर हो जाए।

द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद दुनिया दो हिस्सों में बँट गई थी, एक ओर पश्चिमी लोकतांत्रिक देश थे और दूसरी ओर साम्यवादी (कम्युनिस्ट) देश। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने उस समय अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि युद्ध के बाद के यूरोप पर "लोहे का पर्दा" (आयरन कर्टन) गिर गया है, जिसने पश्चिम और साम्यवादी पूर्व के बीच दीवार खड़ी कर दी है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ यह टकराव सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया। दुनिया दो हिस्सों में बँट गई, जो औपनिवेशिक (कलोनियल) काल के प्रभाव की तरह थी। लेकिन सोवियत संघ के टूटने और विकासशील देशों के उभरते आर्थिक बल बनने के बाद यह पुरानी व्यवस्था धीरे-धीरे बिखरने लगी।

अमेरिका ने जब राष्ट्रपति निक्सन के नेतृत्व में चीन के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए, अपने विदेश नीति सलाहकार हेनरी किसिंजर की पहल पर, उसके बाद से वैश्विक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया।

इसके सामानांतर अमेरिका और सोवियत संघ ने महसूस किया कि परमाणु हथियारों की दौड़ व्यर्थ है, और उन्होंने अपने परमाणु भंडार सीमित करने के लिए कई समझौते किए। इन समझौतों में सबसे प्रसिद्ध परमाणु शस्त्रागार संधि थी, जिसे "स्टार्ट ट्रीटी" कहा जाता है। यह 1990 के दशक से लागू रही और अब समाप्त होने वाली है।

अलास्का के एंकोरेज में अपनी पिछली बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक समझौते के आधार पर परमाणु शस्त्रागार संधि को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। यही वह समय था जब दोनों राष्ट्रपतियों, ट्रंप व पुतिन ने सौहार्दपूर्ण वार्ता की और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा की।

लेकिन उसके बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों में मतभेद बढ़ गए। पुतिन ने युद्ध कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे संबंध फिर बिगड़ गए। अब ट्रम्प यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुतिन सचमुच यूक्रेन में शांति लाना चाहते हैं या नहीं।

अजीब बात यह है कि तीन साल पहले यूक्रेन में शुरू हुई लड़ाई ने अब पूरी दुनिया को टकराव के माहौल में झोंक दिया है। दुनिया भर में आतंकवादी हमले, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ और आम नागरिकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं।

गाज़ा में हुई बर्बरताएँ, पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की युद्धोन्मादी बयानबाज़ी, ट्रम्प के मनमाने सैन्य हमले और अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी, इन सबने मिलकर वैश्विक टकराव का एक भयावह माहौल बना दिया है।

बिहार चुनाव को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल हैं, को निष्कासित करने पर मजबूर होना पडा है।

निष्कासन की यह लहर सभी राजनीतिक दलों में देखी गई है। भाजपा को पिछले कुछ हफ्तों में करीब 20 नेताओं को निष्कासित करना पड़ा, जिनमें काहलगांव विधायक पवन कुमार यादव और चार बार के परुई विधायक अशोक कुमार सिंह शामिल हैं।

जेडीयू ने 16 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार, और पूर्व विधान परिषद सदस्य (एम एल सी) संजय प्रसाद और रणविजय सिंह शामिल हैं। गोकलपुर से चार बार के विधायक रहे गोपाल मंडल को भी पार्टी से बाहर किया गया, और जेडीयू नेतृत्व ने इस सीट से हाल ही में आर जे डी छोड़कर बूलो मंडल को उम्मीदवार बनाया।

राजद ने भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 27 नेताओं को निष्कासित किया। है। निष्कासित नेताओं में पार्टी के मौजूदा विधायक छोटे लाल राय (पारसा) भी शामिल हैं। इसके अलावा, गोबिंदपुर के विधायक मोहम्मद कमरान, और पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, अनिल साहनी, सरोज यादव, और अनिल यादव के साथ-साथ, पूर्व एमएलसी गणेश भारती भी निष्कासित किए गए है।

कांग्रेस विद्रोहियों को बाहर निकालने से बची है। लेकिन पार्टी के भीतर मतभेद खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में पटना हवाई अड्डे पर, पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को एक-दूसरे से लड़ते हुए देखा गया।

निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनावी मैदान में कई विद्रोहियों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यह चुनाव कम से कम अभी तक तो 'लहर रहित' चुनाव माना जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इस स्थिति का आकलन इस प्रकार किया जा रहा है: कड़े मुकाबलों, में जहां जीत का अंतर बहुत कम करना है, विद्रोही या निर्दलीय उम्मीदवार परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर जन सुराग पार्टी जनसभा के उम्मीदवारों को भी थोड़ा सा वोट भी मिलता है, तो यह मुख्य राजनीतिक दलों - राजद, भाजपा, और जेडीयू - के लिए स्थिति को जटिल बना सकता है।

प्र.मंत्री छठ पर्व को यूनैस्को से सांस्कृतिक विरासत घोषित करवाने में जुटे

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एक जनसभा में यह जानकारी दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार छठ महापर्व को युनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिलवाने की कोशिश कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने वोटों के लिए "छठ मैया" का अपमान किया है। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर छठ पूजा को लेकर "नाटक" करने का आरोप लगाने के बाद, मोदी ने यह बयान देकर स्थानीय लोगों को भावनात्मक रूप से उकसाने की कोशिश की है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें हिंदू देवी छठी माता (या स्थानीय बोली में "मैया") की पूजा की जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आपका (यह) बेटा छठी मैया की पूजा दुनिया के सामने कर रहा है, जबकि कांग्रेस और राजद नेता छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार इस प्रकार के अपमान को सहन करेगा? क्या मेरी माताएं, जो निर्जला उपवास करती हैं, इसे सहन करेंगी? पीएम मोदी ने सवाल किया। जनता ने एक स्वर में जोर से "नहीं" कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "राजद और कांग्रेस कितनी बेहया बात कर रहे हैं? उनके लिए छठी मैया की पूजा सिर्फ एक नाटक है, एक मजाक?" उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा अपमान लोगों की स्मृति में सदियों तक रहेगा।" बिहार आत्मसम्मान की भूमि है। बिहार उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने छठ पूजा का अपमान किया है।"

- **बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में छठ पर्व का मुद्दा काफी गर्म है।**
- **प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि वे "छठी मइया" का अपमान कर रहे हैं, जबकि वे खुद छठ पर्व को दुनिया भर में पहचान दिलाना चाहते हैं।**

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908